भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से संबंधित माह नवंबर, 2024 का मासिक सारांश

I. जल जीवन मिशन (जेजेएम)
माह नवंबर 2024 में 7.60 लाख नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं, जिससे अगस्त 2019 में मिशन के शुभारंभ के बाद से यह लगभग 12.09 करोड़ नल जल कनेक्शन हो गया है। दिनांक 30.11.2024 की स्थिति के अनुसार, 19.35 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से लगभग 15.33 करोड़ (79.22%) ग्रामीण परिवारों को नल जल की आपूर्ति मिल रही है। वर्ष 2024-25 में जेजेएम के कार्यान्वयन के लिए 70,162.90 करोड़ रुपये की बजटीय राशि के मुकाबले माह के अंत तक 21,507.73 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

II.स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण- चरण - II
माह नवंबर 2024 के दौरान 3,76,608 व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय (आईएचएचएल) और 3,559 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों (सीएससी) का निर्माण किया गया है। इस अवधि के दौरान 32,000 गांवों ने स्वयं को ओडीएफ प्लस घोषित किया है। माह के दौरान 23,666 गांवों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और 5,409 गांवों को तरल अपशिष्ट प्रबंधन द्वारा कवर किए जाने की सूचना है। वर्ष 2024-25 में एसबीएम (जी) के कार्यान्वयन के लिए 7192.00 करोड़ रुपये की बजटीय राशि के मुकाबले महीने के अंत तक 1869.60 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया गया है।

III. व्यय विभाग ने 1.40 लाख करोड़ रुपये के कुल परिव्यय की अनुमोदित सीमा के भीतर 31 मार्च 2026 तक एक वर्ष की अवधि के लिए एसबीएम (जी) के विस्तार हेतु इस विभाग के अनुरोध पर सहमति व्यक्त की है। वर्तमान में, जल जीवन मिशन के विस्तार के लिए ईएफसी अनुमोदन हेतु मसौदा ज्ञापन पर भी माननीय जल शक्ति मंत्री सक्रिय रूप से विचार कर रहे हैं।

IV. गोबर-धन पहल के एक भाग के रूप में, डीएफएस ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के समन्वय से एक मसौदा समझौता तैयार किया है और गेल तथा बैंकों के साथ साझा किया है, ताकि उत्पादन क्षमता के 60% सुनिश्चित ऑफटेक को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र में बैंकिंग सहायता का विस्तार किया बढ़ाई जा सके, जो विचाराधीन है।

V. नीति आयोग की भागीदारी में दिनांक 06.11.2024 से 20.11.2024 तक जल जागरूकता और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक जल उत्सव अभियान चलाया गया। ध्वजवाहक के रूप में डीसी/डीएम के साथ 20 राज्यों के 20 आकांक्षी जिलों/ब्लॉकों में कार्यान्वित, इस अभियान का उद्देश्य सेवा-रहित क्षेत्रों में पानी से संबंधित चुनौतियों का समाधान करते हुए जल स्थिरता और संरक्षण की संस्कृति को स्थापित करना था।

VI. 12 राज्यों नामत: आंध्र प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड राज्यों के ग्रामीण स्वच्छता के एसीएस/प्रधान सचिव/प्रभारी सचिव तथा मिशन निदेशकों (एसबीएम-जी) के साथ दिनांक 25.11.2024 को सचिव, डीडब्ल्यूएस की अध्यक्षता में वीसी के माध्यम से एसबीएम (जी) के दूसरे चरण की प्रगति की समीक्षा के लिए बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम के प्रभावी और शीघ्र कार्यान्वयन तथा समय-सीमा के भीतर वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए राज्यों को आवश्यक सलाह/सुझाव/टिप्पणियां/इनपुट दिए गए थे।

VII. पूर्वोत्तर राज्यों में एसबीएम (जी) के कार्यान्वयन की समीक्षा बैठक 12.11.2024 को गुवाहाटी, असम में माननीय मंत्री, जल शक्ति की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। पूर्वोत्तर राज्यों के ग्रामीण स्वच्छता के प्रभारी राज्य मंत्रियों ने बैठक में भाग लिया। सचिव डीडब्ल्यूएस और संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक, एसबीएम (जी) ने समीक्षा बैठक में भाग लिया। बैठक में पूर्वोत्तर राज्यों के ग्रामीण स्वच्छता और जल के प्रभारी अपर मुख्य सचिवों/प्रभारी सचिवों ने भी भाग लिया। अधिकारियों/सलाहकारों की टीमों ने क्षेत्र से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए 10 और 11.11.2024 को असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और सिक्किम के कुछ गांवों का भी दौरा किया।

VIII. सचिव, डीडीडब्ल्यूएस ने पंचायती राज मंत्रालय के साथ 08.11.2024 को 'ई-ग्रामस्वराज' पोर्टल के साथ जेजेएम के निगरानी तंत्र के एकीकरण के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की।

IX. एएस एंड एमडी-एनजेजेएम की अध्यक्षता में आरहूस नगर पालिका, डेनमार्क के डेनिश विशेषज्ञ प्रतिनिधिमंडल के साथ एक बैठक दिनांक 08.11.2024 को नई दिल्ली में आयोजित की गई ताकि सतत पेयजल आपूर्ति, एकीकृत जल प्रबंधन और संसाधन के रूप में अपशिष्ट जल संबंधी क्षेत्रों पर चर्चा की जा सके।

X. विभाग ने जेजेएम संबंधी चुनौतियों का निराकरण करने तथा आगे की कार्यनीति पर चर्चा करने हेतु दिनांक 22.11.2024 को नई दिल्ली में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ ग्रामीण जल आपूर्ति संबंधी बुनियादी ढांचे की दीर्घकालिक स्थिरता और आगे की कार्यनीति पर विचार-मंथन सत्र का आयोजन किया।

XI. नवंबर 2024 में, एसपीएम-निवास संस्थान ने जेजेएम और एसबीएम-जी से संबंधित विविध क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए 13 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। जिनमें कुछ प्रमुख प्रशिक्षण कार्यक्रम नल जल सेवा ऐप की प्रभावी कार्यशीलता और उपयोग पर ऑनलाइन लघु पाठ्यक्रम; स्मार्ट ग्रामीण जल प्रबंधन और बुनियादी ढांचे के अनुकूलन के लिए आईओटी का उपयोग करना; ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, तरल अपशिष्ट प्रबंधन और मलीय गाद प्रबंधन तथा हरित राजमार्ग: टिकाऊ सड़कों में प्लास्टिक कचरे का उपयोग शामिल हैं। इन प्रशिक्षणों में विभिन्न राज्यों से 422 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया।

XII. नवंबर 2024 में 13 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 23 ज़िलों में बाहरी पाइपगत जलापूर्ति योजनाओं का दौरा करने के लिये 42 राष्ट्रीय वॉश विशेषज्ञों (एनडब्ल्यूई) को नियोजित किया गया था।

XIII. सहबद्ध मंत्रालयों के साथ पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के लिए अंतर-मंत्रालयी सामंजस्यपरक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक संयुक्त बैठक 28.11.2024 को पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक एसबीएम (जी) और संयुक्त सचिव, जेजेएम ने की तथा पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर), ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी), महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमओडब्ल्यूसीडी), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू), आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए), पर्यटन मंत्रालय (एमओटी), विद्यालयी शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (डीओएसईएल) और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) के प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया।

***